The House then adjourned at four minutes past eleven of the clock.

The House reassembled at twelve of the clock,

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

शिक्षा के लिए 100 दिनों की कार्य योजना

*46. **श्री प्रभात झा**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2019 में नई सरकार के गठन के बाद मंत्रालय द्वारा 100 दिनों की एक कार्य योजना तैयार की गयी थी, जिसमें नई शिक्षा नीति सहित कई विषय शामिल थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्य योजना को निर्धारित समयावधि में अंतिम रूप से क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'): (क) से (घ): विवरण सदन के सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) महोदय, 100 दिन के कार्यक्रम में मुख्य स्कीमों के नाम निम्नलिखित है -

1. **शिक्षकों का प्रशिक्षण** -

   (क) **निष्ठा** - 21 अगस्त, 2019 को 42 लाख स्कूल शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और शैक्षणिक अधिकारियों के लिए राष्ट्रव्यापी एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम 'निष्ठा' की शुरूआत की गई। इसके अलावा, सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों के 41972 शिक्षकों को 819 प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया ।

   (ख) **अर्पित** - इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 10 लाख शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु अर्पित 'ARPIT' ऑनलाइन पोर्टल को लॉंच किया गया । इसके तहत अब तक 1.46 लाख शिक्षक प्रशिक्षण हेतु पंजीकरण करवा चुके हैं।

2. **नये केन्द्रीय विद्यालयों का शुभारंभ** - 20 नये केन्द्रीय विद्यालयों का शुभारंभ किया गया।

3. **केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थांन (शिक्षक कॉडर में आरक्षण) अधिनियम, 2019-** समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में ही केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक कॉडर में आरक्षण), अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत केन्द्रीय उच्च शिक्षण संस्थाओं में नवम्बर के पहले सप्ताह तक 12426 रिक्तियों को विज्ञापित किया गया।

4. **केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2019 -** 17वीं लोक सभा के प्रथम सत्र में ही केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। फलस्वरूप आंध्रप्रदेश में एक नवीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक केन्द्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की शुरूआत की गई है। तत्काल रूप में इन दोनों विश्वविद्यालयों को अस्थाई परिसर से संचालित किया जा रहा है।

5. **प्रतिष्ठित संस्थानों की घोषणा-** 20 विख्यात शैक्षणिक संस्थानों को प्रतिष्ठित संस्थान (Institution of Eminence - IOE) के रूप में घोषित किया गया। इसमें से 10 संस्थाएं सार्वजनिक क्षेत्र की हैं।

6. **प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव) -** 10 अक्तूबर, 2019 को इसकी शुरुआत हुई तथा इसके प्रथम चरण का 23 अक्तूबर को सफलता पूर्वक सम्पन्न किया गया।

7. **नई शिक्षा नीति -** जहां तक नई शिक्षा नीति का प्रश्न है, इसकी शुरूआत वर्तमान सरकार के आने के पहले हो चुकी थी। भारतीय शिक्षा में अगली पीढ़ी के सुधार की व्यवस्था इसमें की जा रही है। इसके प्राप्त मसौदे पर व्यापक परामर्श किया गया। राज्यों के शिक्षा मंत्री एवं विभिन्न राज्यों के सांसदों, हितधारकों, विशेषज्ञों एवं अभिभावकों के साथ विमर्श हो चुका है। इन स्रोतों से प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर नई शिक्षा नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

100 day action plan for education

†*46. SHRI PRABHAT JHA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether a 100 day action plan comprising various topics along with the New Education Policy was prepared by the Ministry after the formation of new Government in May, 2019;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the above mentioned action plan has been finally implemented in due course of time; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The major schemes of the 100 days programme are the following:–

(1) **Teachers training:**

(a) NISHTHA - On 21st August, 2019 a nationwide integrated teachers training programme for 42 lakh teachers, school-heads and educational officers was launched. In addition to this, 41972 teachers associated with schools under CBSE were trained at 819 training centres.

(b) ARPIT - In the area of higher education, to train 10 lakh faculty members, an online portal called ARPIT was launched. Under this about 1.46 lakh faculty members have got themselves registered.

(2) **Inauguration of central schools -** 20 Central schools were inaugurated.

(3) **Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' cadre) Act 2019-** To protect the constitutional right of persons belonging to scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, socially and economically weaker sections of society, in the very first session of 17th Lok Sabha, Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act 2019 was passed by the Parliament. Under this, in Central Higher Educational Institutions, till the first week of November 2019, 12426 vacancies have been advertised.

(4) **Central Universities (Amendment) Act 2019 -** In the very first session of 17th Lok Sabha, Central University (Amendment) Act 2019 was passed by Parliament. As a result of this, a Central University in Andhra Pradesh and a Central Tribal University in Andhra Pradesh have started. As of now, these Universities are being operated from their temporary campuses.

(5) **Declaration of Institution of Eminence -** 20 well known educational institutions have been declared as Institution of Eminence (loE). Out of these, 10 institutions are public institutions.

(6) **Pradhan Mantri Innovative Learning Programme "DHRUV" -** It has been

started on 10th October, 2019 and the first phase successfully completed on 23rd October, 2019.

(7) **New Education Policy -** So far as New Education Policy is concerned, the work on this started before the present Government took over. It sets the tone for the next generation of reforms in the education system of India. A detailed consultation has been done on the draft prepared. Discussions have also been held with the State Education Minister, MPs of different States, stakeholders, experts and parents. After analysis of the suggestions received from these sources, draft for new education policy is being finalized.

MR. CHAIRMAN: Question No. 46. ...*(Interruptions)*... Minister of Human Resource Development. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: आदरणीय सभापति महोदय ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप लोग प्लीज़ बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रभात झा: भारत सरकार के ...(**व्यवधान**)... मानव संसाधन मंत्रालय में मंत्री ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: प्लीज़ बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)...

SHRI B.K. HARIPRASAD: Sir, we have given notice under Rule 267 to discuss the. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: मैं डा. 'निशंक' जी को बधाई देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति के तहत ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए ...(**व्यवधान**)... This is not the way. I will not allow any such thing. ...*(Interruptions)*... Nothing shall go on record. ...*(Interruptions)*... No shouting shall go on record. There are other avenues and opportunities to discuss. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रभात झा: चाहे निष्ठा हो ...(**व्यवधान**)... अर्पित ...(**व्यवधान**)... शुभारंभ करना हो ...(**व्यवधान**)... शैक्षणिक आयोग बनाना हो ...(**व्यवधान**)... वह सब हुआ है ...(**व्यवधान**)... मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वर्तमान में देश की ...(**व्यवधान**)... किन-किन शैक्षणिक संस्थाओं को Institute of Eminence का दर्जा दिया गया है? ...(**व्यवधान**)... क्या उनमें मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं? ...(**व्यवधान**)... यदि नहीं हैं, तो क्या मध्य प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों को Institute of Eminence का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है? ...(**व्यवधान**)...

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक": सभापति जी, हमारे जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं ...(**व्यवधान**)... वे प्रतिष्ठित संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के दस-दस चिह्नित हुए हैं। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान ...(**व्यवधान**)... Institute of Eminence. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I have already told you, give notice under the relevant rule. I would examine it. ...*(Interruptions)*... Please. You have been in power for years. You know the procedure. I need not tell you. I urge you, please save the prestige of the House. ...*(Interruptions)*... Allow other Members the right to express. The other day, you all came to me and I said that Question Hour should be allowed to continue. Now you are disturbing Question Hour. ...*(Interruptions)*...

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" : आईआईटी दिल्ली ...(**व्यवधान**)... आईआईटी मद्रास ...(**व्यवधान**)... आईआईटी खड़गपुर ...(**व्यवधान**)... दिल्ली युनिवर्सिटी विश्वविद्यालय ...(**व्यवधान**)... हैदराबाद विश्वविद्यालय ...(**व्यवधान**)... बीएचयू... वाराणसी ...(**व्यवधान**)... यूपी ...(**व्यवधान**)... अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई ...(**व्यवधान**)... तमिलनाडु ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Nothing is going on record. Why are you wasting your energy? ...*(Interruptions)*...

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" : ...(**व्यवधान**)... श्रीमन्, ये सार्वजनिक क्षेत्र के दस संस्थान हैं, ...(**व्यवधान**)... जबकि निजी क्षेत्र के Manipal Academy of Higher Education. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN; You cannot dictate according to your likings. I have already replied to that. ...*(Interruptions)*...

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक": महोदय, Manipal Academy of Higher Education ...*(Interruptions)*... Birla Institute of Technology and Science, Pilani, राजस्थान में है, Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar, ओडिशा में है ...(**व्यवधान**)... Vellore Institute of Technology, Tamil Nadu में है। ...(**व्यवधान**)... Jamia Hamdard University नई दिल्ली में है ...(**व्यवधान**)... Amrita Vishwa Vidyapeetham, तमिलनाडु में है ...(**व्यवधान**)... भारती संस्थान ...(**व्यवधान**)... है। ...(**व्यवधान**)... सभापति जी, ओ.पी. जिन्दल यूनिवर्सिटी ...(**व्यवधान**)... हरियाणा में है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Do other Members want Question Hour or not? Please tell me. I have no problem. ...*(Interruptions)*... क्वेश्चन ऑवर होना है या नहीं होना है? ...(**व्यवधान**)...

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक" : ये प्रतिष्ठित संस्थान चिह्नित किए गए हैं ...(**व्यवधान**)... जो विश्व की रैंकिंग पर आगे आने के लिए ...(**व्यवधान**)... तैयार हैं। ...(**व्यवधान**)... श्रीमन्, इन संस्थानों के लिए ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Mr. Siva, please sit down. You are on the panel of Vice-Chairmen. ...*(Interruptions)*... The other day, everybody came to me and requested me that Question Hour should be allowed. Don't adjourn it up to 2 o'clock. The Leader of

the Opposition himself said that. If there is an issue, they should come to me, meet me and discuss with me separately. They could give notice under a separate provision and we can think about admitting it. But I would not accept this sort of a dictation in the House that 'you should do it now itself'. Please understand. You have been in power for many years. You know it better than me. That way, I am junior when compared to many of you. ...*(Interruptions)*... I am not joking. I am seriously saying that when compared with some of you, I am junior; there are senior people. So, rules, regulations and procedure have to be followed. ...*(Interruptions)*... Please. Majority of the Members want the Question Hour to continue.

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक": सभापति जी, जैसा कि मैंने बताया है, माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि ये कितने संस्थान हैं और कहाँ-कहाँ हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैंने इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के दस संस्थान और निजी क्षेत्र के दस संस्थानो का प्रदेशवाइज़ उल्लेख किया है। माननीय सदस्य ने पूछना चाहा है कि क्या इसमें मध्य प्रदेश का भी कोई संस्थान है? सभापति जी, मैं उनके प्रश्न के संबंध में यह बताना चाहता हूं कि अभी इसमें मध्य प्रदेश का संस्थान नहीं है, क्योंकि जो ईईसी की कमेटी होती है, उसके कुछ मानक होते हैं और उन्हीं मानकों के आधार पर, जो उन मानकों को प्राप्त करेगा, उन्हीं को ये संस्थान, जो आईओई संस्थान हैं, उनको चिह्नित किया जाता है।

श्री प्रभात झा: सर, 17 नवंबर, 2019 को जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था कि IIT, Delhi, IIT, Mumbai और Indian Institute of Science, Bengaluru को पर्याप्त funding नहीं मिलने के कारण Institute of Eminence के अन्तर्गत योजनाओं का उपयुक्त तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है?

श्री सभापति: मंत्री जी, किसी भी अखबार में जो रिपोर्ट आई, क्या उसके बारे में यहाँ reply दिया जाना है? फिर भी आप देखिए कि इसमें क्या बात है। अखबार में बहुत कुछ आता रहता है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, IIT, Delhi को पर्याप्त फंड दिया गया है। इन संस्थानों को अभी तक टोटल 214 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अभी तक इन तीनों संस्थानों ने फंड को खर्च नहीं किया है। लेकिन यदि आप चाहेंगे, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2018-19 में इन सभी संस्थानों को 43-43 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2019-20 में IIT, Delhi को 50 करोड़ रुपए और दिए गए हैं, जबकि IIT, Mumbai को चूँकि 43 करोड़ रुपए दिए गए थे और उसने कोई खर्च नहीं किया, इसलिए उसको अभी तक और फंड नहीं दिया गया है। हमारे बेंगलुरु का जो संस्थान है, उसको 35 करोड़ रुपए और दिए गए हैं। श्रीमन् जैसे-जैसे ये संस्थान खर्च करते रहेंगे, हम इनको पैसे देते रहेंगे। इनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी।

SHRI VAIKO: Mr. Chairman, Sir, education was in the State List. When we were languishing in the dark dungeon cells, including yourself, that was usurped and swallowed into the Concurrent List. Now this new Education Policy is nothing but a new bulldozer policy. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: You have to ask the question. This is not a speech. ...*(Interruptions)*...

SHRI VAIKO: Did they have serious deliberation and discussion with every State Government on this? How many State Governments opposed this and how many State Governments supported this?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह जो नई शिक्षा नीति आ रही है, इसका जो मसौदा तैयार हो रहा है, मुझे लगता है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा परामर्श हुआ है। इसमें अध्यापक से लेकर छात्र, छात्र से लेकर जन-प्रतिनिधि, सरकार, शिक्षा मंत्री, ब्यूरोक्रेट्स से लेकर विशेषज्ञ सभी सम्मिलित हैं। श्रीमन्, मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिकी से युक्त होगी, सतत विकास के लक्ष्यों से युक्त होगी, विकासोन्मुख होगी, ...**(व्यवधान)**... शोध और अनुसंधान से युक्त होगी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में नवाचार करेगी। ...**(व्यवधान)**...

SHRI VAIKO: I am awaiting for the reply. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Sitting and commenting, as I said yesterday, is like drunken driving.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': गतिशील एवं उद्यमिता ...**(व्यवधान)**... सर्जनात्मक बनाया जाएगा। Happiness और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित किया जाएगा। श्रीमन्, सांस्कृतिक संरक्षण होगा, यह भारत केन्द्रित होगा। श्रीमन्, यह व्यापक रूप में आ रही है।

MR. CHAIRMAN: Vaikoji, you have been in this House for long. You have been in public life. You know when to speak and how to speak. You have to ask him a question and I allowed you. You have some reservation about the Policy. ...*(Interruptions)*... But, please don't go beyond a point and then try to say 'it is bulldozing and all', whatever you don't like. I am the last man to allow bulldozing. You know this.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, the new Education Policy drafted under the Chairmanship of Dr. Kasturirangan has invoked several concerns from various States and stakeholders. There are many things which I cannot elaborate during the Question Hour. Has the

Government addressed those concerns and issues because the new Education Policy is intended to give new level of education to the upcoming generation in competition with the world, at global level. But actually it is like retreating. So, have they taken into consideration the concerns and reservations raised by various stakeholders and finalised the Report after that? When will it be published?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' : श्रीमन्, जैसा मैंने पहले कहा, इसमें व्यापक परामर्श हुआ है। माननीय सदस्य की जो चिंता है, उसके प्रति सरकार भी बखूबी सचेत है और इसलिए इतने व्यापक स्तर पर कस्तूरीरंगन जी की रिपोर्ट आने के बाद उसको public domain में डाला गया। इसमें लगभग दो लाख से भी अधिक सुझाव आए हैं। एक-एक सुझाव का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के सांसदगण, वहाँ के शिक्षा मंत्रियों, वहाँ के शिक्षा सचिव और शिक्षा-शास्त्रियों के साथ हमने अलग-अलग करके भी लगातार विमर्श किया है। श्रीमन्, जितने भी सुझाव आए हैं, उन सुझावों को इसमें समाहित किया गया है। यह आने वाला जो मसौदा है, सबकी सहमति से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से, सभी राज्यों के सांसदों से, जन-प्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श करके उनके सुझावों को समाहित किया जा रहा है।

SHRI VAIKO: How many States have opposed it? ...*(Interruptions)*... You have to protect the Members.

MR. CHAIRMAN: Vaikoji, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: Sir, first of all, I would like to ask the hon. Minister as to what is suggested in the draft National Policy on Education about teaching of children in local languages, in mother tongue, at primary and elementary stages because the Government of Andhra Pradesh has introduced compulsory primary education...

MR. CHAIRMAN: No, no. You should ask a question.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO: What is the policy?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, चूंकि अभी नीति बनने की अवस्था चल रही है और उसका यह मसौदा आया है। जैसा माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या प्राथमिक शिक्षा मातृ भाषा में होगी, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि शुरू से ही, 1968, 1986 और वर्तमान में, इसी नीति को अपनाया गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, वह मातृ भाषा में होनी चाहिए। यही नीति ज्यादा सफल रही है।